

वस्त्र उद्योग में महिला उद्यमिता के अवसर वैशाली सिंह, रश्मी दुबे एवं साक्षी

भूमिका

भारत का वस्त्र उद्योग देश के औद्योगिक उत्पादन एवं निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है, तथा इसमें लगभग 4.5 करोड़ श्रमिक प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। परंपरागत रूप से इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सूत कातने, बुनाई, कढ़ाई एवं सिलाई जैसे कार्यों तक सीमित रही है, परंतु बदलते समय के साथ महिलाएँ अब केवल श्रमिक न रहकर उद्यमी, डिजाइनर एवं व्यवसाय-स्वामी के रूप में भी उभर रही हैं। सरकारी नीतियों, वित्तीय सहायता योजनाओं, डिजिटल बाजार एवं कौशल-विकास कार्यक्रमों के सम्मिलित प्रभाव से वस्त्र एवं परिधान उद्योग आज महिला उद्यमिता के लिए एक अत्यंत संभावनाशील क्षेत्र बनकर उभरा है।

वस्त्र उद्योग में महिलाओं की वर्तमान भागीदारी

वस्त्र एवं परिधान उद्योग भारत में महिला रोजगार के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना के अनुसार हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लगभग 72 प्रतिशत बुनकर महिलाएँ हैं। इसी प्रकार परिधान निर्माण (गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग) इकाइयों में भी महिला कर्मचारियों की भागीदारी बहुत अधिक है — कई बड़े निर्यातमुखी गारमेंट कारखानों में 90 प्रतिशत तक कर्मचारी महिलाएँ हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (2022-23) के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) 37 प्रतिशत रही, जो पिछले सर्वेक्षण से 4.2 प्रतिशत अंक अधिक थी, और 2023-24 में यह दर

बढ़कर 41.7 प्रतिशत तक पहुँच गई। विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र इस वृद्धि में अपेक्षाकृत अधिक योगदान देने वाले क्षेत्रों में शामिल हैं। यह आँकड़े दर्शाते हैं कि श्रमिक स्तर पर महिलाओं की व्यापक भागीदारी पहले से मौजूद है, परंतु अब आवश्यकता इसे उद्यमशीलता एवं नेतृत्व के स्तर तक ले जाने की है।

वस्त्र उद्योग में महिला उद्यमिता के प्रमुख अवसर

- ✦ **हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्यम:** पारंपरिक बुनाई, कढ़ाई (चिकनकारी, फुलकारी, कांथा) एवं ब्लॉक-प्रिंटिंग कौशल रखने वाली ग्रामीण महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से सामूहिक उद्यम स्थापित कर सकती हैं।
- ✦ **बुटीक एवं परिधान डिजाइनिंग:** स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर अनुकूलित (customised) परिधान, ब्राइडल वियर एवं फैशन डिजाइनिंग व्यवसाय।
- ✦ **टेक्सटाइल प्रिंटिंग, डाइंग एवं फिनिशिंग यूनिट:** प्राकृतिक रंगाई (natural dyeing) एवं इको-प्रिंटिंग जैसे सतत विकल्पों में विशेष संभावना।
- ✦ **ई-कॉमर्स आधारित वस्त्र व्यवसाय:** सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मार्केटप्लेस के माध्यम से कम पूंजी में घर से व्यवसाय आरंभ करने की सुविधा।

वैशाली सिंह, रश्मी दुबे एवं साक्षी

वस्त्र एवं परिधान विज्ञान विभाग

सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय

चन्द्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.)

- सतत एवं उच्च-मूल्य वस्त्र उत्पाद: जूट, हेम्प, बाँस एवं जैविक कपास से बने पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों के विशिष्ट (niche) बाज़ार में उद्यमिता।
- वस्त्र निर्यात एवं आपूर्ति शृंखला प्रबंधन: प्रशिक्षित एवं शिक्षित महिलाएँ छोटी विनिर्माण इकाइयों की मालकिन एवं निर्यातक के रूप में भी आगे आ रही हैं।

सरकारी योजनाएँ एवं सहायता ढाँचा

भारत सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु कई विशेष योजनाएँ लागू की हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत नवंबर 2023 तक स्वीकृत कुल 44.46 करोड़ ऋणों में से लगभग 69 प्रतिशत महिलाओं को दिए गए। स्टैंड-अप इंडिया योजना, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का ग्रीनफील्ड ऋण उपलब्ध कराती है, से अब तक लगभग 1.34 लाख उद्यमियों को सहायता मिली है, जिनमें 81 प्रतिशत महिलाएँ हैं। वस्त्र मंत्रालय की समर्थ योजना (कौशल विकास हेतु) एवं एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (SITP) भी अप्रत्यक्ष रूप से महिला उद्यमियों को अवसंरचना एवं प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराती हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बजट 2025-26 में नए उद्यमियों, विशेषकर महिलाओं, को अगले पाँच वर्षों में 2 करोड़ रुपये तक के सावधि ऋण की सुविधा देने की नई पहल की घोषणा की गई है।

चुनौतियाँ

- वित्तीय पहुँच: बैंक ऋण हेतु आवश्यक गारंटी एवं दस्तावेजीकरण की जटिलता के कारण ग्रामीण महिला उद्यमियों को अक्सर औपचारिक वित्त प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

- कौशल एवं डिज़ाइन प्रशिक्षण की सीमित उपलब्धता, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में।
- घरेलू एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों के साथ व्यवसाय संचालन का संतुलन बनाना।
- बाज़ार तक सीधी पहुँच का अभाव, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता एवं कम लाभ मार्जिन की समस्या बनी रहती है।
- डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता की कमी, जो ऑनलाइन व्यवसाय विस्तार में बाधा बनती है।

आगे की राह: सुझाव

- वस्त्र विज्ञान एवं गृह विज्ञान के पाठ्यक्रमों में उद्यमिता-कौशल (व्यवसाय योजना, विपणन, वित्तीय प्रबंधन) को औपचारिक रूप से जोड़ा जाए।
- स्वयं सहायता समूहों को सहकारी उद्यमों एवं ब्रांड निर्माण की दिशा में सुदृढ़ किया जाए।
- महिला उद्यमियों हेतु आसान एवं संपार्श्विक-मुक्त (collateral-free) ऋण प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए।
- ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों एवं सरकारी डिजिटल मंचों पर महिला-नेतृत्व वाले वस्त्र ब्रांड्स को प्राथमिकता एवं मार्गदर्शन दिया जाए।
- क्षेत्रीय स्तर पर मेंटरशिप एवं नेटवर्किंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, जिससे अनुभवी महिला उद्यमी नई उद्यमियों का मार्गदर्शन कर सकें।

निष्कर्ष

वस्त्र उद्योग, जो पहले से ही लाखों महिलाओं को रोजगार प्रदान करता है, अब उद्यमशीलता के एक सशक्त मंच के रूप में भी विकसित हो रहा है। सरकारी योजनाओं, कौशल-विकास पहलों एवं डिजिटल बाज़ार की सुविधाओं ने महिलाओं के लिए श्रमिक से उद्यमी

बनने की राह को अपेक्षाकृत सुगम बनाया है। यदि वित्तीय पहुँच, प्रशिक्षण एवं बाज़ार-संपर्क से जुड़ी चुनौतियों का समुचित समाधान किया जाए, तो वस्त्र क्षेत्र महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण-शहरी अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम बन सकता है।

संदर्भ (References)

1. Angel One (2025) — 'भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना: शीर्ष 6 सरकारी ऋण योजनाएँ', angelone.in
2. Startup India — 'महिला उद्यमिता', startupindia.gov.in/hindi
3. ORF Hindi (2025) — 'बजट 2025-26 और महिलाओं का सशक्तिकरण', orfonline.org/hindi
4. Drishti IAS — 'महिलाओं में निवेश और भारत की समृद्धि', drishtias.com
5. Drishti IAS — 'भारत में महिला श्रम बल भागीदारी', drishtias.com
6. ORF Hindi — 'भारत में महिला कामगार: उभरते रुझान और निरीक्षण', orfonline.org/hindi
7. The Print Hindi (2023) — 'भोपाल की नई गारमेंट फैक्ट्री में मिल रहीं काफी नौकरियाँ', hindi.theprint.in
8. Drishti IAS — 'भारत में वस्त्र उद्योग', drishtias.com/hindi/daily-news-analysis/india-textile-sector

